

प्रेषक,

डा0एम0सी0 जोशी,  
अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,  
देहरादून।

ऊर्जा विभाग,

देहरादून दिनांक 7 अप्रैल, 2004

विषय:- ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु AREP योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में REC से प्राप्त ऋण के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में संलग्न विवरणानुसार (संलग्नक-I, II, III) विभिन्न जनपदों में उनके सम्मुख अंकित संख्या में ग्रामों/तोंकों का विद्युतीकरण किये जाने हेतु व्यय वहन के लिये प्रथम किरत के रूप में श्री राज्यपाल महोदय रु0 6,51,42,000/- (रु0 छ करोड़ इक्यावन लाख ब्यालिस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वातन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। जनपदवार स्वीकृत धनराशि का विवरण संलग्न है। (संलग्नक-IV)

2. उक्त धनराशि AREP योजनान्तर्गत REC से ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विभिन्न योजना कांड संख्या के रूप में स्वीकृत कुल ऋण रु0 65,14,34,000/- के सापेक्ष अवमुक्त प्रथम किरत के सापेक्ष राज्य सरकार से उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को REC की सभी शर्तों के प्राविधानानुसार उपलब्ध करायी जा रही है। REC से प्राप्त ऋण के सम्बन्ध में राज्य शासन, UPCL (लाभार्थी) एवं REC के मध्य हस्ताक्षर किये गये अनुबन्ध एवं हार्डपॉथिकेशन अनुबन्ध की सभी शर्तों का पालन UPCL द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि AREP योजनान्तर्गत REC से स्वीकृत निम्नलिखित ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के सापेक्ष चिन्हित गांवों/तोंकों के विद्युतीकरण एवं सम्बन्धित योजना में वर्णित विद्युतीकरण से सम्बन्धित कार्यों के व्यय वहन हेतु इस प्रकार किया जायेगा कि स्वीकृत योजना में उल्लिखित न्यूनतम समयावधि में विद्युतीकरण एवं वर्णित सभी कार्यों को शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा।

क0सं0	योजना कोड संख्या	कुल ऋण धनराशि	जनपद	ग्रामों की संख्या	तोंकों की संख्या
1-	580001 से 580007 तक	4351.57	रुद्रप्रयाग	23	-
			उत्तरकाशी	27	-
			चमोली	89	-
			अल्मोड़ा	37	-
			बागेश्वर	55	-
			चम्पावत	21	-
			मिथौरागढ़	67	-
2-	580008 से 580009 तक	426.65	देहरादून	-	49
			टिहरी	-	42
3-	580010 से 580018 तक	1736.12	पौड़ी	124	-
			टिहरी	83	-
	योग:-	6514.34		526	91

4. उक्त जनपदों के सम्मुख ग्रामों/तोकों की संख्या के सापेक्ष विद्युतीकरण हेतु योजना में चुने गये ग्रामों/तोकों की सूची तत्काल शासन, सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जायेगी तथा सम्बन्धित ग्राम के ग्राम प्रधान को भी सूचित किया जायेगा कि उनके किस गांव/तोक का विद्युतीकरण इस योजना के अधीन कब तक किये जाने का लक्ष्य है, वहां न्यूनतम कितने विद्युत संयोजन किस श्रेणी के दिये जाने हैं एवं क्या-क्या अन्य कार्य सम्मिलित हैं। सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को भी श्रेणीवार विद्युत संयोजन दिये जाने एवं किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाय।
5. उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० द्वारा प्रत्येक दशा में REC से सम्बन्धित योजनाओं के लिये ऋण स्वीकृति की सूचना सम्बन्धी REC के पत्रों के संलग्नक A व B (प्रतियां संलग्न) में इंगित सभी शर्तों वही शत प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी। इसमें त्रुटि की दशा में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० एवं उनके सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
6. UPCL द्वारा योजना के अधीन विद्युतीकरण का कार्य समय से पूर्ण कर REC से तत्काल एवं समय से प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत कर सम्पूर्ण योजना के लिये स्वीकृत ऋण के समतुल्य धनराशि की समय से प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी एवं जहां सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी, उसे UPCL द्वारा अपने श्रोतों से वहन किया जायेगा।
7. ग्रामों/तोकों के विद्युतीकरण/योजना में वर्णित सुविधाओं के सृजन के पश्चात् सम्बन्धित ग्राम प्रधान से नियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर REC व शासन को प्रेषित किया जायेगा, जैसा कि योजना की शर्तों में वर्णित है। साथ ही विद्युतीकरण उपरान्त ग्रामों/तोकों की सूची समयान्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जायेगी, जो अपने स्तर से इसका सत्यापन कर सकेंगे। जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्तानुसार सत्यापन में पाई गई किसी त्रुटि या कमी तथा सत्यापन का विवरण UPCL एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. REC द्वारा स्वीकृत योजना में सम्बन्धित ग्रामों/तोकों के विद्युतीकरण के साथ-साथ योजना में इंगित निर्धारित संख्या में विद्युत संयोजनों/भार की प्राप्ति, जैसा कि संलग्नक-1, II, III में वर्णित है, भी अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।
9. नियत अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर ब्याज की अतिरिक्त देयता की जिम्मेदारी UPCL/UPCL के सम्बन्धित अधिकारियों की होगी।
10. ऋण एवं ब्याज की समय से वापसी उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा ऋण वापसी के विस्तृत विवरण (साक्ष्यों सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। नोरेटोरियम की अवधि में देय ब्याज का समय से भुगतान भी उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में भुगतान के विवरण साक्ष्य सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. नियत अवधि पर भुगतान/वापसी न करने पर 2.75 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज दण्ड के रूप में अतिरिक्त देय होगा तथा 6 माह से अधिक भुगतान/वापसी में ढूँक की दशा में योजना का विशेष स्वरूप सम्पादित हो जायेगा, जिस दशा में ऋण पर सामान्य ब्याज (ऋण स्वीकृति के समय प्रचलित) लगेगा। अतः उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० द्वारा प्रत्येक दशा में योजना का संपादन/क्रियन्वयन निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अनुसार समय से करते हुये नियत तिथि तक किस्त व ब्याज की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. योजना में प्रथम किस्त आहरण के बाद यदि कोई प्रतिपूर्ति दावा एक वर्ष की अवधि में REC को प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तो प्रथम किस्त में अवमुक्त सन्पूर्ण ऋण की राशि को ब्याज/दण्ड ब्याज सहित REC को वापस किया जायेगा।
13. उक्त स्वीकृत राशि पर ब्याज की देयता 29 मार्च, 2004 से आगणित होगी, जिस तिथि को REC से यह राशि अवमुक्त हुई है।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित समय में उपयोग कर उस धनराशि से योजनावार कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार व राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा, ताकि आगामी किस्त की भारत सरकार से प्राप्त होने में विलम्ब न हो।



15. किस्तों एवं ब्याज की वापसी नियत तिथि से पूर्व अवश्य कर दिया जाय एवं इस हेतु नोटिस/सूचना का इन्तजार न किया जाय। धनराशि सीधे REC को भुगतान करते हुये शासन को सूचना ससमय दी जाय।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण बीजक पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त कोषागार में प्रस्तुत कर किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि लेखानुदान के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801-विजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-05-पारिषण एवं वितरण-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपकर्मा व अन्य उपकर्मा में निवेश-आयोजनागत-01-केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ-104-उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० को REC से ऋण-30-निवेश/ऋण के नामे खाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के असासकीय सं०- 05/वि०अनु०-3/2004, दिनांक 05 अप्रैल, 2004 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।  
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,  
(डा०एम०सी० जोशी)  
अपर सचिव

संख्या: (1961/04) 556/नौ-3-ऊ/RECAREP/03, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल।
- 2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मंत्र्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
- 3- निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा० राज्य मंत्री के संज्ञान में लाने हेतु।
- 4- जिलाधिकारी, देहरादून/समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, उत्तरांचल, देहरादून।
- 7- सचिव, नियोजन विभाग।
- 8- वित्त अनुभाग-3।
- 9- प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,  
(डा०एम०सी० जोशी)  
अपर सचिव

**RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED**  
(A Government of India Enterprise)

21/11/2005 - A

**Annexure (A)**

**Terms & Condition (GENERAL) applicable to loan for  
P: VE(SG) category**

1. Unless the Corporation otherwise agrees in writing, the loan of the scheme shall be disbursed over a period of one year from the date of award of contract.

The loan would be disbursed to the State Govt, which would make the funds available to the executing agency under the terms and conditions as sanctioned by REC.

The State Government/concerned Central Power Utility would undertake to arrange for necessary budget provision in the Annual Budget(s) of the State/concerned State Power Utilities for Prompt repayment of loan to REC and shall also undertake to ensure to arrange payment of monthly installment towards loan repayment together with interest as applicable on requisition from the Corporation before the last date of the month.

Additionally the State Government concerned Central Power Utility shall ensure creation of charge in favour of the Corporation by way of hypothecation of future assets to be created out of the project loan sanctioned by REC. Hypothecation of assets will have the same meaning as defined in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

2. The disbursement procedure shall be as follows:
  - a) Separate bank account has to be opened by borrower for payments - monthly statement and certificate to be furnished to REC
  - b) Each disbursement would be based on utilisation certificate and proof of the payments against the earlier instalment.
  - c) The first instalment up to 10% of the loan amount shall be released on execution of loan documents and compliance of stipulated terms and conditions in the sanction letter.
  - d) The second and subsequent instalment of loan shall be released on reimbursement basis depending upon the progress of works indicated in the claims preferred by the borrower after pro-rata adjustments of initial advance of 1<sup>st</sup> instalment.



- e) The final 10% of the loan amount shall be released after final field monitoring and on submission of confirmation letter from Gram Pramukh/Sarpanch indicating name and date of Electrification of New Village/Hamlet/Dalit Bastis and on completion of "defects correction period" if assigned to the turn key contractor. The deviation, if any, shall be considered at the time of submission of final claim as per REC guidelines.
3. The State Government shall complete the work relating to the scheme within a period of one year from the date of award of contract. The Corporation at its discretion may agree to the request of the State Govt. to extend the period of implementation of the project/scheme.
4. The State Government shall submit its application for the loan duly supported by such certificates and authentications in the forms as may be prescribed for the purpose by the Corporation.
5. The State Government shall execute such agreements, Hypothecation Deed, and documents as may be prescribed for the purpose by the Corporation.
6. The Corporation shall be free and fully empowered not to disburse any further loan, if it is found to its satisfaction that the loan or loans already disbursed have not been properly utilized by the State Govt. or it has committed any default in meeting its obligation and commitments to the Corporation in terms of the provisions of the agreement.
7. The loan shall also be subject to such further terms and conditions as may be laid down in the forms of agreement executed or to be executed by the State Government.
8. The State Govt. agrees that :
- i) It shall ensure provision of Dalit Bastis in the scheme area have been invariably included for electrification under P:VE(SG) scheme.
  - ii) It shall also ensure provision for release of Kutir Jyoti connections to all the households of the rural poor in the villages covered or at least 10 households of the rural poor in each village has been made under P:VE(SG) scheme.
  - iii) It shall undertake that whenever a village is declared electrified, the name of village shall be intimated to the MPs, MLAs of the area and Gram Pramukh/Sarpanch of the village and acknowledgement in confirmation of village having been electrified, will be obtained from Gram Pramukh/Sarpanch of the village by the Power Deptt. and reported to REC and CEA.



9. It will be open to the Rural Electrification Corporation to depute its officers and staff for the inspection of matters relating to the scheme, to have access to such books and records of the State Govt./Power utility as may be deemed necessary by the inspecting Staff. The State Govt./Power Utility shall also furnish to the Corporation such reports on its working either in general or in specific relation to the project financed by the Corporation from time to time including status of future assets being created out of Projects Loan.

Annexure (U)

10. The loan shall also be subject to such further terms and conditions as may be laid down in the form of the Loan Agreement and Hypothecation Deed to be executed by the State Govt. and the executing agency.

11. The State Govt./Power Utility shall have to certify that:

a) No provision has been made in the State Plan outlays for financing of the scheme.

b) It will not, for meeting any part of the capital outlay for the works included in which the scheme, raise borrowings from other sources such as LIC or Commercial Banks.

c) In the event of the State Govt./Power Utility proposing to promote or implement a scheme of consumer deposits for the same purpose, viz. of financing the capital outlay envisaged under the scheme, it will do so only after obtaining the permission of the Corporation and

vd) The scheme has been formulated on the latest cost data approved by the Corporation.

12. Notwithstanding anything stated hereinbefore it will be open to the Corporation to periodically reduce or enhance the rate of interest in respect of the loan instalments not disbursed up to the date of such revision in the rate of interest. The revision in the rate of interest shall take effect from such date as may be notified by the Corporation in this behalf.

13. Consultant may be appointed by the State Govts., at their discretion to assist them in formulation of project, bidding documents, evaluation of award of contract and monitoring of progress of work. The Consultant so appointed shall also be responsible for reporting monthly progress of work to the Ministry of Power, Central Electricity Authority and Rural Electrification Corporation through their respective State Govts. In accordance with the scheme stipulations.



21/11/2015 - B

**RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED**  
**( A Government of India Enterprise )**

The period of moratorium for repayment shall be 13 years from the 1st day of the month of disbursement of the loan.

**Annexure (B)** by the State Govt. will be sanctioned from the date of disbursement of the loan.

**Terms & Condition applicable to loan for**

**P: VE(SG) category** shall pay interest at 3% per annum for the entire period of moratorium. The repayment of loan shall be as follows:

1. The State Government shall pay interest on the loan at 3% per annum for the entire period of 13 years from the date of disbursement of the first instalment of loan. Interest will be charged quarterly till the end of the repayment period.
2. In the event of any instalment being paid, the interest to be charged and received as above will be considered for waiver by REC and refunded to the Borrower, or adjusted against repayment of principal loan amount, which would make the scheme actually interest free.
3. If the scheme is not fully and successfully implemented within the period of one year from the date of disbursement of first instalment of loan and on award of turn-key contract, or within the extended period for implementation of the project/scheme beyond the period of one year as may be agreed to by REC at its discretion under special circumstances on the merits of each case, at the specific request of the State Govt./Borrower, then the concessional/nominal interest rate as applicable on the above special scheme for Village/Hamlet Electrification and Dalit Bastis Electrification would continue to be payable during the entire period of loan as notified above in para 1.
4. Waiver of the interest shall be considered by REC, only if scheme is successfully and fully completed as per schedule. The completion of scheme shall be considered successful on the basis of the fulfilment of the following:
  - i) The scheme is executed on turn-key basis if not envisaged to be executed departmentally.
  - ii) The scheme is completed within the time-frame as provided in the sanction letter.
  - iii) The scheme has achieved the desired goal i.e. electrification of all villages/Hamlets/Dalit Bastis as envisaged in the scheme to be supported by the list of such Villages/Hamlets/Dalit Bastis (Village-wise).
  - iv) Additional expenditure, beyond the loan amount sanctioned by REC under the scheme, if required to complete the electrification of all the Dalit Bastis covered in the scheme, will have to be borne by the State Government from their own funds.



5. The period of moratorium for repayment of principal shall be three years from the 15<sup>th</sup> day of the month of disbursement of first instalment of loan but the entire loan shall be repaid by the State Govt. within a period of 13 years (including three years moratorium) from the date of disbursement of the first instalment of loan.

6. The State Govt. shall pay interest as indicated in clause(1) above during the period of moratorium. The repayment of principal thereafter will be effected on the basis of equal annual instalments and interest shall be calculated at the rates prescribed in clause(1) above on the amount outstanding.

7. In the event of any instalment of interest or of principal not being paid to the Corporation by the State Govt. on the due dates, as indicated in clause (1) and (5) above, the State Govt. shall pay to the Corporation a penal rate of compound interest @ 2.75% p.a. above and in addition to the rates of interest stated in clause (1) above. However, if the default persists for more than six months, the special status of the schemes shall be withdrawn and the loan shall stand reverted to normal scheme rate of interest i.e. the base rates prevailing at the time of sanction of scheme, which at present is 9% p.a.

8. Total interest charged shall be adjusted against the last instalment of repayment. No interest is payable to the borrower on the amount of interest refundable.

9. The State Govt. shall also pay levy of interest tax at the prevalent rate per annum as notified by Govt. of India or as may be modified from time to time on the gross interest earnings per annum on this scheme.

10. The Corporation may agree at the request of the State Govt. to extend the period of disbursement of loan and implementation of the project/scheme by one year which will be in addition to the original period for implementation of the scheme. However, the period of moratorium on repayment of loan will continue to remain the same as indicated in clause 5 above and will not be effected by the extension in the period of disbursement of loans and implementation of the project.

11. In the event of the loan documents for drawal of the amount for the first phase duly completed in all respects not being submitted within 6 months from the date of letter conveying sanction of the loan or such further extended period as may be allowed by the Corporation in its absolute discretion the sanction of the loan shall stand withdrawn.

12. In the event of drawal of only first instalment and no further claim has been received by REC for work done if any even though the period of one year after release of first instalment of loan has lapsed, the entire loan of 1<sup>st</sup> instalment will be repaid back to REC alongwith interest/penal interest till the date of payment.



5/10/74 -  
ANNE KILPATRICK

ESTIMATED FUTURE PRODUCTION FROM 1974-1975 FOR COMPARISON OF THE PROPOSED FARMING

STATE UTILIZATION

No	Name of the scheme	No of sheep for each location	LT Industrial				Domestic				Commercial				Bovine				Total				Construction work proposed			
			No		No		No		No		No		No		No		No		No		No		No		No	
			1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Bardoli & other 22 villages in Kutch district	23	11	41	1378	1378	91	182	0	0	1478	1509	36	48	80	30	403	1778								
2	Thal & other 28 villages in Kutch district	27	18	60	1436	1436	58	112	0	0	1500	1509	16	151	17	100	20	2094								
3	Kutch & other 68 villages in Kutch district	65	2	6	2083	2083	125	254	0	0	2192	2224	32	212	36	146	30	2884								
4	Kutch & other 23 villages in Kutch district	27	13	48	707	707	38	73	0	0	758	801	68	87	88	45	30	1066								
5	Kutch & other 54 villages in Kutch district	55	25	54	1726	1726	140	280	0	0	1966	2234	3	223	43	84	13	2167								
6	Kutch & other 20 villages in Kutch district	21	8	34	478	478	15	33	0	0	503	522	24	55	25	20	00	733								
7	Kutch & other 68 villages in Kutch district	67	136	511	1887	1887	174	348	0	0	2175	2726	36	183	00	706	25	3328								
8	Total	119	112	151	5557	5557	643	1282	0	0	30610	31735	121	340	15	378	10									

Scheme under 500000 - 500000

## SANCTION PARAMETERS PROPOSED UNDER PHE(SG) SCHEMES FOR CONSIDERATION OF THE SCREENING COMMITTEE

STATE: UTTARANCHAL

Sl. No.	Name of the scheme/ District	No. of Virgin Habitats for electrification	S E R V I C E S   P R O P O S E D						C o n s t r u c t i o n   w o r k s   p r o p o s e d					
			I I Industrial		D o m e s t i c		C o m m e r c i a l		S t r e e t   l i g h t		H T line K m.	L T line K m.	No./ capacity	Dist. S/S KVA
			No	KW	No	KW	No	KW	No	KW				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Chakrata and 3 other blocks in Dehradun dist.	49	0	0	740	740	36	72	0	0	28	35	31/25 18/16	1063
2	Jaunpur and 8 other blocks in Tehri dist.	42	0	0	678	678	31	62	0	0	32	58	18/25 30/16	930
Total:			0	0	1418	1418	67	134	0	0	60	93	1495	1662

Scheme Code 580008 and 580009



**SAFETY AND SECURITY SERVICES PROPOSED UNDER P.V. STATE SCHEME FOR CONSTRUCTION OF THE SCHEMES COMMITTEE**

STATE: UTTARANCHAL

Sl. No.	Name of the scheme District	No. of villages for electrification	SERVICES PROPOSED								Street light		Total		Construction works proposed			
			LT Substation		Domestic		Commercial		No	KW	No	KW	No	KW	Ht line Km.	Lt line Km.	No of urgency	MVA
			No	KW	No	KW	No	KW										
1			1	1	1	1	1	1	10	11	14	13	16	17	18	19	20	21
1	Rahmatal and Naryanda blocks in Pauri dist.	28	0	0	410	410	12	30	0	0	422	442	38.20	40.00	9/25	16/16	481	
2	Jahanghal block in Pauri dist.	27	0	0	445	445	27	54	0	0	472	499	40.00	43.00	2/25	25/16	499	
3	Kangra and 5 other blocks in Pauri dist.	14	0	0	74	74	0	0	0	0	74	74	10.00	15.00	14/16		294	
4	Varkaswar block in Pauri dist.	10	0	0	350	350	24	48	0	0	374	398	35.00	30.00	4/25	15/16	340	
5	Thalassan & Veenankhal blocks in Pauri dist.	12	0	0	180	180	10	20	0	0	200	210	30.00	30.00	5/25	8/16	253	
6	Chamba and 4 other blocks in Tehri dist.	35	0	0	554	554	23	46	0	0	581	604	35.00	30.00	1/03	11/25	604	
7	Jaunpur & Nandranand blocks in Tehri dist.	21	0	0	338	338	19	38	0	0	367	376	28.00	34.00	11/25	10/16	435	
8	Shingara block in Tehri dist.	27	0	0	558	558	33	66	0	0	590	624	44.00	35.00	18/25	9/03	594	
9	Surgada & Dargu blocks in Pauri dist.	20	0	0	400	400	50	99	0	0	478	500	50.00	40.00	4/25	22/16	452	
	Total	207	0	0	3387	3387	177	354	0	0	3669	3741						

Scheme code 50 00 10 or 50 00 10

## RELEASE ADVICE

Rout 12

State Name : UTTARANCHAL STATE GOVT.

Voucher No : 1

Particulars :

Dated : 29/03/2004

Nature Of Transaction : Cash

Sl. No.	District Name	Scheme Code	Check Code	Category	Instt No.	Released Amt.
1	RODRAPRAYG	58000100	9	P-VE (SG)		3111000.00
2	UTTARKASHI	58000200	5	P-VE (SG)		7146000.00
3	CHAMOLI	58000300	1	P-VE (SG)		9682000.00
4	ALMORA	58000400	8	P-VE (SG)		3913000.00
5	BAGESHWAR	58000500	4	P-VE (SG)		9314000.00
6	CHAMPAWAT	58000600	1	P-VE (SG)		2373000.00
7	PITHORAGARH	58000700	7	P-VE (SG)		8067000.00
8	DEHRADUN	58000800	3	P-HE (SG)		1905000.00
9	TEHR	58000900	0	P-HE (SG)		2361000.00
10	PAURI	58001000	8	P-VE (SG)		2115000.00
11	PAURI	58001100	4	P-VE (SG)		1959000.00
12	PAURI	58001200	1	P-VE (SG)		595000.00
13	PAURI	58001300	7	P-VE (SG)		2075000.00
14	PAURI	58001400	3	P-VE (SG)		1578000.00
15	TEHRI	58001500	0	P-VE (SG)		2326000.00
16	TEHRI	58001600	6	P-VE (SG)		1931000.00
17	TEHRI	58001700	2	P-VE (SG)		2335000.00
18	PAURI	58001800	9	P-VE (SG)		2396000.00

Page Total : 65142000.00

Cumulative Total : 65142000.00